दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

SJU Social Justice Union

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 25 अगस्त 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक- 325

मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म कर जम्मू-कश्मीर को भी भारत में विलय कर पटेल के अधूरे कार्यों को पूरा किया:शाह

» सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी का 70वां दीक्षांत समारोह

हैदराबाद (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय पुलिस सेवा के 70वें दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि आज का मौका आनंद तथा उत्साह से भरा हुआ है क्योंकि सरदार पटेल के नाम से स्थापित नेशनल पुलिस अकादमी की दीक्षांत परेड के बाद 103 पुलिस ऑफिसर्स को उनकी अपने उज्जवल कैरियर की शुरुआत करनी है।

उन्होंने बताया कि हैदराबाद एक ऐतिहासिक जगह है जहां इस पुलिस एकेडमी का निर्माण किया गया है। आजादी के बाद 630 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का अकल्पनीय कठोर काम जब सरदार पटेल को दिया गया तो एक के बाद एक रियासत जुड़ती गई किंतु उस वक्त के हैदराबाद के निजाम भारतीय संघ के साथ अपनी विलीनीकरण को मान्यता नहीं दे रहे थे और सरदार पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा भारतीय संघ का भाग बना। उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए आगे कहा कि धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर 630 रियासतों के साथ नहीं जुड सका और तब से सबको लगता रहा कि कुछ न कुछ छूट गया है। इस कार्य को आज के प्रधानमंत्री और भारत के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण किया गया और भारतीय संसद ने धारा 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा को भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने का जिम्मा दिया था इसलिए आज जो भी अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने जा रहे हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो जिस प्रदेश में भी जाएंगे, हमेशा सरदार पटेल की उस उक्ति को ध्यान में रखेंगे। उनका कहना था कि सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट को भारतीय हितों का रक्षक बताया है। शाह का कहना था कि हमारे संविधान के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को दो हिस्सों में को बांटा गया है। एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद और विधान मंडलों के अंदर नीतियों और कानूनों का निर्माण करते हैं दूसरे भारतीय सिविल सेवा के सभी अधिकारी नीतियों को नीचे तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए और सिविल सर्वेंट दोनों को संविधान की सेवा करने का मौका मिलता है किंतु एक को केवल 5 साल के लिए अवसर प्राप्त होता है और दूसरे को 60 वर्ष की आयु होने तक मौका मिलता है जो निश्चित रूप से गर्व की बात है। शाह ने कहा कि आप पूरी तन्मयता और लक्ष्यों के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर सफल हुए, तब केवल शुरूआत थी असली परीक्षा अब होगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी चुनौतियां आएंगी। उनका कहना था कि आज देश के सामने आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, साइबर क्राइम आदि को कंट्रोल करने के साथ-साथ पड़ोसी देशों द्वारा खड़ी की गई चुनौतियां भी शामिल हैं। शाह ने कहा कि जब तक देश आंतरिक रूप से सुरक्षित नहीं होगा, विकसित नहीं हो सकता और प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। शाह ने कहा कि संविधान को स्प्रिट को समझना और उसके अनुरूप भयमुक्त होकर कार्य करना करना सच्चे आईपीएस ऑफिसर का दायित्व होता है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रोबेशनर्स को नसीहत देते हुए कहा कि आज की गई प्रतिज्ञा सदैव दिल में रखें और जब तक आपकी सेवा समाप्त नहीं होती है तब तक रोज सुबह उस प्रतिज्ञा को याद करें। उन्होंने कहा कि आज से आपकी लक्ष्यपूर्ति का रास्ता शुरू हो रहा है और महान भारत देश को दुनिया में उसके गौरवशाली स्थान पर पहुंचाने में आपको महत्वपूर्ण योगदान देना है। उनका कहना था कि समृद्ध, सुशिक्षित भारत हमारा लक्ष्य होना चाहिए तथा हमें भारत की विशाल, विविधतापूर्ण सस्कृति को संरक्षित रखकर उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आप जिस पुलिस बल का नेतृत्व करने जा रहे हैं उसके 33 हजार से ज्यादा पुलिस जवानों ने देश की सुरक्षा में अपनी जान की आहुति दी है और वह हमसे आशा करते हैं कि हम मां भारती को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा कर उनके बलिदान को सार्थक करने का काम करें।

महत्वपूर्ण एवं खास

राहुल समेत विपक्ष के 11 नेता कश्मीर के लिए प्लेन में हुए सवार

» श्रीनगर में एंट्री पर लगा बैन

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता कश्मीर का दौरे के लिए विमान में सवार हो गए है। इस बीच खबर है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने डेलिगेशन को श्रीनगर आने से मना किया है। उन्होंने कहा है कि डेलिगेशन को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव, द्रविण मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) नेता तिरुची शिवा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माजीद मेनन, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी. राजा, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता दिनेश त्रिवेदी तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा शामिल हैं। विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद वहां जमीनी हकीकत को देखने के लिए जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल हाल ही में राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा गांधी को घाटी में आकर यहां के जमीनी हकीकत जानने के लिए दिये गये आमंत्रण के बाद जम्मू-कश्मीर जा रहा है।

उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें : सियोल

सियोल। उत्तर कोरिया ने शनिवार को पूर्वी सागर में कम दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बात की जानकारी दी। ऐसे में सियोल और वाशिंगटन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास समाप्त होने के बाद भी तनाव बढ़ गया। योनहाप न्यूज एजेंसी ने संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के बयान का हवाला देते हुए बताया कि दक्षिण हैमयोंग प्रांत के सोंदोक शहर से सुबह 6.45 बजे और सुबह 7.02 बजे पूर्वी सागर में मिसाइलों को दागा गया और दोनों ने 97 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 380 किलो मीटर की उड़ान भरी और उनकी अधिकतम गति मैक 6.5 के आसपास थी। दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया अधिकारियों द्वारा उनके(मिसाइल) सटीक प्रकार का विश्लेषण करने की बात कहते हुए जेसीएस ने बयान दिया, हमारी सेना अतिरिक्त प्रक्षेपण के मामले पर निगरानी कर रही है और स्थिति पर तत्परता बनाए हुए है। शनिवार का प्रक्षेपण 25 जुलाई के बाद से सातवां प्रक्षेपण है। अंतिम मिसाइल 16 अगस्त को दागी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया इन प्रक्षेपणों के जरिए नई प्रकार की छोटी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसमें इस्कैंडर और यूएस के आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम (एटीएसीएमएस) के वर्जन शामिल हैं।

नहीं रहे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, एम्स में ली अंतिम सांस

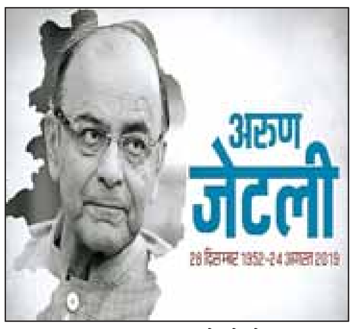

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद दोपहर 12 बजकर 07 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली. वह 66 वर्ष के थे। अरुण जेटली को सांस लेने में दिक्कत के कारण एम्स में 9 अगस्त को भर्ती कराया गया था. पिछले कुछ दिनों से उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही थी. बता दें कि जेटली काफी समय से एक के बाद एक बीमारी से लड़ रहे थे. इसी के चलते उन्होंने लोकसभा चुनाव, 2019 में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का आग्रह किया था.

जेटली ने पत्र में लिखा था कि 18 महीने से मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है. मैंने चुनाव प्रचार की सभी जिम्मेदारियों को निभाया. अब अपनी सेहत और इलाज पर ध्यान देना चाहता हूं. दरअसल, उन्हें अप्रैल, 2017 में एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वह डायलसिस पर थे. इसके बाद 14 मई, 2018 को दिल्ली के एम्स में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ.

उनकी गैरमौजूदगी में रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके बाद जेटली ने 23 अगस्त, 2018 को फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली.

कोर्ट ने 3 बैंक कर्मचारियों को 4 साल के लिए जेल भेजा

नईदिल्ली (आरएनएस)। नोटबंदी के दौरान अवैध रूप से धन के लेन-देन के एक मामले में संभवतः पहली बार दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पीएनबी के तीन अधिकारियों को चार वर्ष जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि उनके कृत्यों से उस संस्थान पर धब्बा लगा जिसमें वे काम करते हुए आगे बढ़े हैं. विशेष न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों रामानंद गुप्ता, भुवनेश कुमार जुल्का और जितेन्दर वीर अरोड़ा को 10.51 लाख रुपये की वैध राशि को गलत तरीके से नोटबंदी की राशि के रूप में दिखाने और इसे अनधिकृत और अवैध रूप से बदलने के लिए दोषी ठहराया.

अदालत ने कहा, दोषी के बैंक अधिकारी होने के कारण उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करें. दोषियों के कृत्य ने संस्थान पर धब्बा लगा दिया जिसमें काम करते हुए वे वरिष्ठ अधिकारी के पद तक पहुंचे. यह नोटबंदी के बाद बैंक अधिकारियों द्वारा शक्ति के दुरूपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रतीत होता है.

अदालत ने उन्हें भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ धारा 409 (आपराधिक विश्वासभंजन), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों को मूल दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करना), 477 ए (खाते में धोखाधड़ी) के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2), धारा 13(1) (डी) (नौकरशा द्वारा आपराधिक आचरण) के तहत दोषी ठहराया. अभियोजन के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा के उप सर्कल प्रमुख ने पांच अप्रैल 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें दावा किया गया कि नोटबंदी के दौरान (दस नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 तक) बैंक की सिविल लाइंस शाखा में दो बार कुछ फर्जी रिकॉर्ड कम्प्यूटर, कोर बैंक सॉल्यूशन (सीबीएस) में डाला गया, जो जमाकर्ताओं द्वारा भरे गए मूल वाउचर के विपरीत थे.

पीएम मोदी को आज मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्राउन प्रिंस संग होगी द्विपक्षीय वार्ता

अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे। फ्रांस की यात्रा के बाद यूएई का दौरा उनका त्रिकोणीय राष्ट्र दौरे का दूसरा चरण है। पिछले चार वर्षों में यह उनकी चौथी यूएई की यात्रा है। मोदी को इस दौरान यूएई का सर्वोच्च नागरिक पुरूस्कार से भी नवाज़ा जाएगा।

इससे जुड़े एक सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि इस पुरस्कार को लेकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह हमारी बढ़ती भागीदारी का एक सबूत है। यह भारत की 1.3 अरब जनता का सम्मान होगा। मोदी आज अबू धाबी के राजा और सेना के उप सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह यहां भारत के रूपए कार्ड को भी लांच करेंगे तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि यूएई के राष्ट्रपति ने खलीफा बिन ज़ायेद नाह्यान ने इस वर्ष के अप्रैल माह में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मोदी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के चलते उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। यूएई के बाद मोदी अपने दौरे के आखिरी चरण के लिए शनिवार शाम बहरीन के लिए रवाना होंगे।

जॉनसन, ट्रम्प ने वैश्विक व्यापार के संबंध में चर्चा की

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जी-7 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ विदेश नीति और वैश्विक व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की है। जॉनसन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बैठक हुई।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जॉनसन फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने की प्रतीक्षा में हैं।

गौरतलब है कि जी-7 शिखर सम्मेलन ऐसे समय होने जा रहा है , जब ब्रेक्जिट की समयसीमा पूरी होने में दो महीने शेष रह गये हैं। जॉनसन ने प्रतिबद्धता जतायी है कि उनका देश यूरोपीय संघ (ईयू) को समय सीमा तक छोड़ देगा, भले ही सरकार ब्रूसेल्स के साथ नए ब्रेक्सिट सौदे पर पहुंचती है।

ब्राजीलियाई राष्ट्रपति ने अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए भेजी सेना

ब्रासीलिया। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो ने सेना को अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने में मदद करने के आदेश दिए हैं। बीबीसी ने शनिवार को बताया कि बोलसोनारो द्वारा जारी फरमान में प्रशासन को सीमाई, आदिवासी और संरक्षित इलाकों में सेना की तैनाती करने के लिए कहा गया है। यूरोपीय नेताओं के दबाव के बाद यह घोषणा सामने आई है।

गौरतलब है कि फ्रांस और आयरलैंड ने कहा था कि वे तब तक दक्षिणी अमेरिकी देश के साथ व्यापार सौदे को मंजूरी नहीं देंगे जब तक कि वह अमेजन में लगी आग से निपटने के लिए कुछ नहीं करता। फिनलैंड के वित्त मंत्री ने भी यूरोपीय संघ से ब्राजील के बीफ आयात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करने के लिए कहा है।

पर्यावरण समूहों ने आग से निपटने की मांग करते हुए शुक्रवार को ब्राजील के कई शहरों में प्रदर्शन किए। लंदन, बर्लिन, मुंबई और पेरिस सहित दुनिया भर में ब्राजील के दूतावासों के बाहर भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी लॉरा विलारेस हाउस (33) ने बीबीसी ब्राजील को बताया, हम यहां लंदन में भी आसमान काला होने देने के लिए खड़ा होकर इंतजार नहीं करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन को ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है।

इमरान खान ने जर्मनी से मांगी मदद

» कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का नया पैंतरा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से कश्मीर मुद्दे पर फोन पर बातचीत की। विदेश दफ्तर ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तत्काल कार्रवाई की जिम्मेदारी है।

विदेश कार्यालय के मुताबिक, मर्केल ने कहा कि जर्मनी हालात पर करीब से नज़र बनाए हुए है। उन्होंने तनाव कम करने तथा मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अहमियत को रेखांकित किया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ-साफ बता दिया है कि जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को हटाना उसका अंदरूनी मामला है। साथ में उसने पाकिस्तान को असलियत स्वीकार करने की भी सलाह दी थी।

विदेश दफ्तर ने बताया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद को कश्मीर मुद्दे पर च्जानकारी दी। उसने बताया कि कुरैशी ने मालदीव से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की गुजारिश की।

शाहिद ने कुरैशी से कहा कि मालदीव मानता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंध में भारत का फैसला उसका आंतरिक मामला है। माले में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शाहिद ने टेलीफोन कॉल के लिए कुरैशी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान तथा भारत, दोनों मालदीव के करीबी दोस्त हैं और द्विपक्षीय साझेदार हैं।

शाहिद ने देशों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में हल करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। कुरैशी ने अपने जापानी समकक्ष तारो कोनो से भी टेलीफोन पर बातचीत की तथा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की।

भिवंडी में चार मंजिला इमारत गिरी, दो लोगों की मौत, कई लोग फंसे

महाराष्ट्र (आरएनएस)। महाराष्ट्र के थाने जिले के भिवंडी के शांति नगर इलाके में शुक्रवार देर रात एक चार मंजिला इमारत अचानक गिर गई। जानकारी अनुसार इमारत के मलबे में दबे चार लोगों को बचाया गया था। मलबे में से निकाले गए लोगों में से दो की मौत हो गई है, जबकि पांच लोग घायल हैं। हालांकि अभी मलबे में कई और लोगों के दबे होने की संभावना है।

बताया गया है कि शांति नगर स्थित यह इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और उसे खाली करा लिया गया था लेकिन कुछ लोग वापस उसमें चले गए जिससे वे हादसे का शिकार हो गए। दमकल और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

भिवंडी-निजामपुर महानगर पालिका के कमिश्नर अशोक रणखंब ने घटना के बाद बताया था कि मलबे में से चार लोगों को निकाला गया जिनमें से एक की मौत हो गई थी और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में एक घायल की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जिस वक्त घटना हुई इस जर्जर इमारत को खाली कराया जा रहा था।